

प्रेषक,

डी०एस० गवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक २० सितम्बर, 2016
विषय:- जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील बाजपुर में ३३/११ के०वी० विद्युत उप केन्द्र, इटवा की स्थापना हेतु ४२ X ४५ वर्गफुट भूमि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिं. को सशुल्क पट्टे पर आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-२८११/सात-स०भ०३०/2016 दिनांक-२८.०७.२०१६ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद ऊधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर के ग्राम इटवा के खाता सं०-२११ के खसरा सं०-१०७मि० रकबा ४२ X ४५ वर्गफुट श्रेणी-५(३)ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को शासनादेश सं०-२५८/१६(१)/७३-राजस्व-१ दि०-०९.०५.१९८४, यथासंशोधित शासनादेश संख्या-१६९५/९-१-१(६०)/९३-२८०-रा०-१ दिनांक-१२.०९.१९९७ तथा शासनादेश सं०-१११५/XVIII(II)/2016-18(184)/2015 दिनांक-१५.०६.२०१६ में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की मालगुजारी के १५० गुने के बराबर धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिं. को पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने की सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं।

१. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

२. प्रश्नगत जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-१३२ एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

३. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-९.५.१९८४ के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

४. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-११३२/२०११ (एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-३१०९/२०११ श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील सं०-४३६/२०११/SLP(C) NO. 2020३/२००७ झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि०-जनवरी, २०११ में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

५. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। उसी के लिए किया जायेगा।

6. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नरेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

8. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

10. भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

11. संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी०एस० गर्जाल)
सचिव।

पृ०प०सं- २०९९ / XVIII(ii) / 2016-18(38) / 2016 तददिनांकित
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी सीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०पी० जोशी)
अपर सचिव।